Statement

Status of pending Projects as on 21-2-1994

Sl. No.	Name of the Project	Date of Receipt	Reasons for pendency
1	Sri Sailam Left Bank Canal Project.	December, 93	Considered by the Committee and additional information sought for received recently.
2	Lime stone Mine attached to Tandur Cement plant of Cement Corporation of India.	March 93	Considered by the Committee clarification awaited.
3	Manuguru Shaft Block-I Singareni Collieries Co. Ltd. (SCCL)	January, 93	Do.
4	Manuguru OCP-IV SCCL.	March, 93	Recommended by Expert Committee linked to Forestry clearance.

Environmental aspects of the reliance petrochemicals Ltd., Gujarat

1025. SHRI N. GIRI PRASAD :
SHRI CHATURANAND MISHRA :

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the public interest litigations (PIL) filed in the Gujarat High Court challenging the environmental aspects of the proposed Reliance Petrochemicals Ltd. refinery project at Jamnagar district of Saurashtra region in Gujarat; and

(b) If so, what are the details thereof and Union Government's stand on the project ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH) : (a) Yes, Sir.

(b) Writ Petitions filed in the High Court of Gujarat against the proposed refinery are under consideration of the Hon'ble Court. Government have not yet taken a decision in the matter as the requisite environmental impact assessment and other related reports required for environmental clearance of the project in question are still under preparation.

देश में रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए किये गये उपाय

1026. **श्री सुन्दर सिंह भण्डारी :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेगिस्तान को फैलने से रोकने के लिए पिछले तीन वर्षों में किये गये प्रयासों का ब्यौरा क्या है और ये प्रयास कहां-कहां किये गये हैं और इन प्रयासों पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ;

(ख) इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किये जा रहे हैं ; और

(ग) रेगिस्तान के प्रसार को रोकने हेतु भारतीय विशेषज्ञों ने क्या सुझाव दिये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) भारत सरकार रेगिस्तान पारि-प्रणाली के अवक्रमण को रोकने के लिए अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है । इसमें शामिल हैं--मरुस्थल विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और वानिकी विकास कार्यक्रम । वर्तमान में क्रमशः जापान

और यूरोपीय आर्थिक समुदाय की बाह्य सहायता से राजस्थान और हरियाणा राज्यों में अरावली पर्वत के विकास के लिए दो वानिकी कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं । पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के तहत की गई प्रगति के ब्यौरे इस प्रकार से है :—

व्यय (लाख रुपए)

क्रम सं०	राज्य	1990–91	1991–92	1992–93
	मरुस्थल विकास कार्यक्रम			
1.	गुजरात	254 48	280.47	**208.82**
2.	हरियाणा	470.40	438.09	**468.92**
3.	हिमाचल प्रदेश	202 01	189.74	**229.01**
4.	जम्मू और कश्मीर	309 29	305.33	296.78
5.	राजस्थान	4568.77	3649.32	3647.58
	जोड़ :	5915 95	4862.95	4851.11

व्यय (लाख रुपए)

क्रम सं०	राज्य	1990–91	1991–92	1992–93
	सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम			
1	आन्ध्र प्रदेश	1134 66	1324.51	1479.47
2.	बिहार	665 97	565.45	579.51
3	गुजरात	830 36	736.37	737.68
4.	हरियाणा	152.37	141.36	142.14
5	जम्मू और कश्मीर	289 50	331.23	332.29
6	कर्नाटक	1140.02	1197.40	1272.39
7	मध्य प्रदेश	678.58	953.01	685.34
8	महाराष्ट्र	1266.18	1284 23	1217.66
9	उड़ीसा	545.47	726.29	563.41
10	राजस्थान	647.01	485.09	635.70
11	तमिलनाडु	739.38	670.92	630.34
12	उत्तर प्रदेश	1237.56	1363.54	1271.36
13	पश्चिम बंगाल	471.11	307.19	296.73
	जोड़	9908.17	10086.59	9954.02

अरावली पर्वत-माला, राजस्थान में वनीकरण (ओ०ई०सी०एफ०, जापान से सहायता प्राप्त)

इस परियोजना को अप्रैल, 1992 से पांच वर्ष की अवधि के लिए 166.9 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से शुरु किया गया है। दिसम्बर 1993 तक किया गया व्यय 28.97 करोड़ रुपये का है। दिसम्बर, 1993 तक 40,340 हेक्टेयर क्षेत्र को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है।

वित्तीय उपलब्धि

1992-93	14.618 करोड़ रुपए
1993-94 (दिसम्बर/93)	14.349 करोड़ रुपए

अरावली पर्वत-माला, हरियाणा में सामान्य भूमि का पुनर्वास (यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सहायता प्राप्त)

इस परियोजना को हरियाणा के चार दक्षिणी जिलों अर्थात् भिवानी, महेन्द्रगढ़, गुड़गांव और फरीदाबाद में 1990 से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का परिव्यय 48 करोड़ रुपए का है। इसमें दिसम्बर 1993 तक 18000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है और 30.92 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है।

वित्तीय उपलब्धि

1990-91	3.00 करोड़ रुपए
1991-92	9.524 करोड़ रुपए
1992-93	9.546 करोड़ रुपए
1993-94	8.852 करोड़ रुपए

(ख) भारत सरकार मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य-योजना तैयार कर रही है। रियो में 1992 के दौरान स्वीकृत एजेण्डा 21 के तहत मरुस्थलीकरण का सामना करना एक प्रमुख क्षेत्र है।

विभिन्न कार्यक्रम क्षेत्र जिनके लिए सामुहिक कार्रवाई अपेक्षित है उनमें मरुस्थलीकरण संबंधी जानकारी का सुदृढ़ीकरण, समन्वित भूमि उपयोग विकास, गरीबी उन्मूलन, सूखा तैयारी विकास कार्य, व्यापक मरुस्थलीकरण रोधी कार्यक्रम तैयार करना तथा मरुस्थलीकरण नियंत्रण में लोकप्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने से संबंधित समन्वित विकास कार्यक्रम शामिल हैं।

वर्तमान में भारत मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने संबंधी अंतर-सरकारी परक्राम्य समिति से एक कन्वेंशन के बारे में विचार-विमर्श करने में लगा हुआ है।

(ग) मरुस्थल के फैलाव पर निगरानी के लिए विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझावों में शुष्क और अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में भूमि की उत्पादकता में सुधार करना, विद्यमान प्राकृतिक वानस्पतिक बायोमास प्रबंधन, पुनः वनीकरण मृदा और नमी संरक्षण उपाय, बालू के टीलों पर नियंत्रण, वायु रोधी और आश्रय-पट्टियां, चारा/घास विकास, कृषि वानिकी, वन चरागाह, ऊर्जा (विशेषकर काष्ठ ईंधन) की विविधता और सार्थक निर्माण, समुदाय व्यवस्थित वानिकी आदि शामिल हैं।

Pollution in Delhi

1027. SHRI GOVINDRAO ADIK : Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Delhi is the fourth most polluted city in the world so far as the environmental and noise pollutions are concerned ;

(b) If so, what are the details thereof ;

(c) what measures Government have taken so far or propose to take to curb the menace of pollution especially caused by 20 lakh odd vehicles on Delhi roads which emit th